

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
4. प्रो. (डॉ.) ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

**1. Case No 8301/2021 Shri Ashish Singh S/o Shri Dule Singh Raghuvanshi, R/o, Village - Jamodi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.750 ha. (Stone - 12000 cum per annum, Murrum - 12000 cum per annum) (Khasra No. 213/3, 225/3), Village - Jamodi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) Consultant - Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 213/3, 225/3), Village - Jamodi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) 1.750 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 489वीं दिनांक 12/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति की 561वीं बैठक दिनांक 21/03/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

उत्तर-पूर्व दिशा में 325 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 290 मीटर पर व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक तथा 290 मीटर पूर्व एवं 485 मीटर उत्तर दिशा में पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई. आर. में शामिल किया गया है ।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना तथा वचन पत्र कि वृक्षारोपण प्रथम 02 वर्ष पूर्ण कर लिया जावेगा ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -12,000 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष एवं मुरुम-12,000 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.10 लाख एवं रिकरिंग 02.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख :-

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	व्यय रु.
1.	जमोड़ी गांव में रोड की मरम्मत की जाएगी	1,00,000
2.	ग्राम जमोड़ी क माध्यमिक स्कूल में शुद्ध पैयजल क लिए वॉटरफिल्टर लगाया जायगा	15,000
3.	ग्राम जमोड़ी में गर्मी क दिनों में गांव वालो क लिए शुद्ध पैयजल क लिए 2 टैंकर लगाया जायगा	15,000
4.	ग्राम जमोड़ी में वर्ष में 2 बार चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन एवं दवाओं का वितरण किया जायगा	20,000
कुल योग		1,50,000

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बरियर ज़ोन में तीन लाइनों में किया जायगा )	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, कस्टार चिरोल, जंगल जलझी, सिस्सो आदि।	600
2	पट्टा क्षेप बाह्य अप्रोच रोड का दोनों (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	600
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	900
योग			2100

2. **Case No 8730/2021 M/s Sunny Paint & Tar Products, 12-A, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for "Expansion of Paint & Varnishes Manufacturing Plant" at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore (MP). Env. Cons:- M/s. Gurung Environment Solutions Pvt. Ltd Jaipur, Raj.**

This is a case of Prior Environment Clearance for "Expansion of Paint & Varnishes Manufacturing Plant" at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore (MP) Cat. 5(f) Synthetic organic chemicals industry. The proposed project falls under item no 5(f) i.e. Synthetic organic chemicals hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site.

The case was presented by the PP Shri Sunny Dhamija and their Env. Consultant M/s. Mr. Kapil Singh M/s. Gurung Environment Solutions Pvt. Ltd. Jaipur in the SEAC 489<sup>th</sup> meeting dated 12.03.2021, wherein PP stated following salient features and other details of the project .

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

M/s. Sunny Paint & Tar Products (An ISO Certified Company) was established in the year of 1989. Company is leading Manufacturer of an extensive array of, Oil Alkyds Resins, Thermosetting Acrylic Resins, Amino Resins, Rosin Derivatives, Polyamide Resin, Amino Resins, etc. Sunny Paint have a sound infrastructure, which helps in the smooth and systematic execution of all production related tasks. It is equipped with advanced machinery and cutting-edge technology that ensures swift rate of production. Plant has a state-of-the-art infrastructure that is fully equipped with the world class amenities providing with a resourceful environment. One of the units of Sunny Paint is in Indore, MP. Indore unit is located at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, Madhya Pradesh-452001 in an area of 1394 sqm. It is an operational unit engaged in Manufacturing of different kind of Paint, Tar and Varnishes. The unit is only for formulation. Unit has valid consent to operate issued by MPPCB vide Consent no. AWH86616 valid upto 31.12.2021. Being a formulation unit, environmental clearance is not applicable to the existing unit.

The project of M/s Sunny Paint & Tar Products located in Plot No. A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, Madhya Pradesh- 452001 for manufacturing of 10,000 MT of synthetic resin (Alkyd Resin & Maleic/Phenolic Resin) with existing formulation unit. The unit configuration and capacity of existing project is given as below

Sl.No.	Name	Existing Units		Proposed Units		Total (Existing +Proposed)	
		Configuration	Production (TPA)	Configuration	Production (TPA)	Configuration	Production (TPA)
1	Bitumen Primer	-	105	-	0	-	105
2	Ceiling Compound	-	105	-	0	-	105
3	Distemper Dry and Oil Bound	-	60	-	0	-	60
4	Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide	-	30	-	2970	-	3000
5	Expansion Joint Filler Board	-	3000	-	0	-	3000
6	French	-	6	-	0	-	6

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

	Polish						
7	Tarfelt	-	24000 nos.	-	0	-	24000
8	Varnish Terfaintine	-	12	-	0	-	12
9	Resin	-	0	-	10000	-	10000

The details of the raw material requirement for the proposed project/ expansion cum proposed project along with its source and mode of transportation is given as below:

Sr. No.	Name of Raw Materials	Quantity (MT/MT)
1	<i>Alkyd Resin</i>	
1	Rosin Oil	0.4
2	Pentaerythritol	0.084
3	Glycerine	0.079
4	Phthalic Anhydride	0.205
5	Maleic Anhydride	0.018
6	Benzoic acid	0.011
7	Caustic Soda	0.001
8	Triphenyl Phosphate	0.001
9	Hypo Phosphorous Acid	0.001
10	Xylene	0.02
11	MTO	0.22
2	<i>Maleic/Phenolic Resin</i>	
1	Rosin	0.833
2	Pentaerythritol	0.05
3	Glycerine	0.056
4	Bisphenol	0.056
5	Paraformaldehyde	0.039
6	Triphenyl Phosphate	0.001
7	Maleic Anhydride/Phenol	0.077

The water requirement for the project after expansion is estimated as 12 KLD, out of which 12 KLD of freshwater requirement will be obtained from the private tankers.

- The power requirement for the project is estimated as 125 HP MW which will be obtained from Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL).

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- The cost of the project is Rs 1.54 Crores. The employment generation from the project is 60 no.
- Summary of violation under EIA, 2006/court case/show cause/direction if any, related to the project under consideration shall be furnished - Not Applicable
- Name of the EIA consultant: M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd. [S.No. 111; List of ACOs with their Certificate No. NABET/EIA/2023/RA0192 (Valid till 19.01.2023).

During presentation PP submitted that they are seeking EC for Resin and their other products are non EC products. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with along with following additional TORs as annexed in annexure-D:

1. Justify the expansion wrt to plant area of 1394 SQM and existing and proposed facility to be depicted on layout map on suitable scale.
2. Plant layout with legible labeling of each facility and area should be provided on A3 size paper.
3. Explore the possibility of getting water supply through IMC in place of water tankers.
4. Compliance of CTO duly authenticated by Regional Officer, MP Pollution Control Board.
5. Explore the possibility of clean fuel for boiler, discuss if any additional boiler is required.
6. Current status of HW and Fly ash management & disposal plan is to be submitted in the EIA report
7. MSDS of all chemicals (reactants, products and intermediates) should be provided with the EIA report.
8. Current status and disposal of HW & fly ash management plan is to be submitted in the EIA report.
9. Submit mass balance with chemical commercial and common names.
10. Percentage of Solvent recovery if any.
11. PP should explore possibility of using Bio-fuel based technology in boilers.
12. Chemical storage plan as per their compatibility and storage area containment plan shall be discussed in the EIA report.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in in the SEAC 489<sup>th</sup> meeting dated 12.03.2021, wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

The EIA was presented by the PP Shri Sunny Dhamija and their Env. Consultant M/s. Mr. Kapil Singh M/s. Gurung Environment Solutions Pvt. Ltd. Jaipur before the committee; during discussion following details of this project was submitted by the PP:

- The proposal is for Environmental Clearance for “Expansion of Paint & Varnishes Manufacturing Plant” located at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, Madhya Pradesh-452001 by M/s M/s Sunny Paint & Tar Products.
- The industry is involved in manufacturing of the several products like Bitumen Primer, Ceiling Compound, Distemper Dry and Oil Bound, Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide, Expansion Joint Filler Board, French Polish, Tareelt, Varnish Turpentine. The unit is operational in accordance with Consent to Operate granted by Madhya Pradesh Pollution Control Board vide Consent No. AWH-86616 dated 28.03.2021 (valid upto 31.12.2024).
- Now, company has proposed to manufacture 10,000 MT of Synthetic Resin (Alkyd Resin & Maleic/Phenolic Resin) along with the enhancement of few of the existing products in the existing plant.
- Unit is spread over an area of 1394 Sqm. The proposed expansion shall be done within the existing premises.
- Project being a Small scale Industry located in industrial area, it is exempted from Public Hearing.
- Project at Glance is mentioned below:

S. No.	Particular	Unit	Existing	Proposed	After Expansion
1.	Total Plot Area	Sqm	1394	0	1394
2.	Green belt area	Sqm	-	512	512
3.	Fresh Water Requirement	KLD	1	11	12
4.	Wastewater Generation - Effluent	KLD	0.8	2.0	2.8
5.	Wastewater generation- Domestic	KLD	0.8	1.7	2.5
6.	Power Requirement	HP	75	50	125
7.	Power Backup	KVA	125	0	125
8.	Manpower Requirement	No.	15	45	60
	Permanent		15	45	50
	Contractual		0	10	10
9.	Project cost	Rs. Cr	0.79	0.75	1.54
10.	Capacity of Boiler	Lac KCal	6	-	6
11.	Fuel (for Boiler) (Coal)	TPD	0.5	0.5	1

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

- Freshwater requirement of the project after expansion will be 12 KLD sourced from private tankers. The wastewater generation from the industrial process will be 2 KLD which will be sent to the CETP for treatment and final disposal. The domestic wastewater generation will be 2.5 KLD which will be disposed into septic tanks via soak pit.
- The power requirement for the proposed expansion will be 125 HP will be supplied through M.P. Paschim Kshetra Vidhyut Vitaran Company Limited, Indore. Existing DG Set of 125 kVA will be used in the plant during emergency failure.
- The source of air pollution from existing and proposed expansion is mentioned below:

S. No.	Stack Attached	Capacity	Fuel Used	Stack Height	APCM	Expected Pollutants
<b>Existing</b>						
1	Boiler	6 Lac K Calories/hr	Bio Briquette	30	Bag Filter, Dust Collector and Natural Draft	PM, Sox, NOx
2	DG Set	125 KVA	HSD	11	Stack & Natural Draft	PM, Sox, NOx

During presentation, PP submitted that they are seeking EC for Resin and Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide being these are EC products and rest are non EC products. After detail discussion committee has asked the PP to submit the following information:

1. Commitment from the PP that 96% solvent recovery will be achieved.
2. Revised EMP and CSR as suggested by the committee during presentation.
3. Revised Plantation Scheme along with its species and total area coverage for plantation should be atleast 33% around and along the periphery of plot.
4. Justification for Tarfelt quantity with size.
5. Justification for Tarfelt quantity with size.
6. Details of plantation done till date & what was planted as condition of plantation is not compiled as per consent condition.
7. Revised Mass balance as suggested by the committee.
8. Mass balance & chemical reaction for Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide.
9. Correct chemical reaction w.r.t. alkayd resin.
10. Legible Lay pout plan.
11. Quantify carbon foot print after the expansion of products.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

**3. Case No 8021/2020 M/s R.J.Traders, Prop. Shri Nabi Baksh, S/o SHri Raheem Baksh, R/o, Naya Bazar No. 02, Dist. Damoh, MP Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 6.50 ha. (2400 cum per annum) (Khasra No. 36), Village - Jamuniya, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar, (MP) EIA Consultant: In-Situ Enviro Care, Bhopal.**

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 36), Village - Jamuniya, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar, (MP) 6.50 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 473वीं दिनांक 07/01/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 80 लगे हुए हैं जिसमें से 35 पेड़ काटे जायेंगे और उनके एवज 350 पेड़ अतिरिक्त लगाये जायेंगे । खदान क्षेत्र पूर्व एवं उत्तर-पूर्व दिशा में 295 मीटर पर नहर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा जनसुनवाई के दौरान आवागमन के मार्गों का रख-रखाव, वृक्षरोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जावे हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ लीज क्षेत्र में पेड़ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊंचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- ✓ स्लरी मैनेजमेंट प्लॉन ।
- ✓ टॉपस्वाइल की मात्रा एवं मैनेजमेंट प्लॉन ।
- ✓ ग्राउण्ड वाटर टेवल की वास्तविक स्थिति ।
- ✓ ओ.बी. और टोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षरोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. जिसमें प्रस्तावित अतिरिक्त वृक्षरोपण का बजट ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट-2400 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.60 लाख एवं रिकरिंग 08.64 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख :-

साल	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	फल देने वाले पौधों, (पौधों की संख्या 1000, दर-50रु प्रति पौधा) इमली, आंवला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरुद, मुनगा, आम, नींबू, जामून एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ग्राम जमुनिया में एक वर्ष में वितरित किये जाएंगे। (यह गतिविधि मध्य प्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत की जाएगी।)	50,000
2	ग्राम जमुनिया की आंगनबाड़ी को दो वर्ष के लिये गोद लिया जावेगा और उसका खर्च वहन किया जावेगा।	2,00,000
3	जमुनिया गांव में पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	50,000
योग		3,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, खमार, शीशम, बरगद, आम, महुआ, इमली, चिरोल, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	6000
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, आम, शीशम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, गुआवा, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
योग			7800

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

**4. Case No 8054/2020 M/s A.R.Traders, Prop. Shri Baseem Ahmad S/o Shri Mohammad Yusuf, R/o, Naya Bazar No. 02, Dist. Damoh, MP – 470661 Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 6.0 ha. (2400 cum per annum) (Khasra No. 36), Village - Jamuniya, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar, (MP) EIA Consultant: In-Situ Enviro Care, Bhopal.**

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 36), Village - Jamuniya, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar, (MP) 6.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 476वीं दिनांक 29/01/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 40 पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें से 25 पेड़ काटे जायेंगे और उनके एवज 250 पेड़ अतिरिक्त लगाये जायेंगे । इसी प्रकार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 60 मीटर पर नहर है, अतः कम से कम 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा जनसुनवाई के दौरान आस-पास के लोगों को आवागमन के लिए रास्ते का रख-रखाव एवं पेय जल की व्यवस्था की जावे हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खदान क्षेत्र की पूर्व दिशा में 60 मीटर पर नहर है, अतः कम से कम 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाये ।
- ✓ लीज क्षेत्र में पेड़ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- ✓ स्लरी मैनेजमेंट प्लॉन ।
- ✓ टॉपस्वाइल की मात्रा एवं मैनेजमेंट प्लॉन ।
- ✓ ग्राउण्ड वाटर टेवल की वास्तविक स्थिति ।
- ✓ ओ.बी. और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. जिसमें प्रस्तावित अतिरिक्त वृक्षारोपण का बजट ।

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

- ✓ खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 60 मीटर पर नहर है, अतः 40 मीटर सेट-बैक (नॉन माईनिंग क्षेत्र) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट – 2400 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.55 लाख एवं रिकरिंग 08.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख :-

साल	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	फल देने वाले पौधों, (पौधों की संख्या 1000, दर-50रु प्रति पौधा) इमली, आंवला, हर्षा, बहेडा, सीताफल, अमरुद, मुनगा, आम, नींबू, जामून एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ग्राम जमुनिया में एक वर्ष में वितरित किये जाएंगे। (यह गतिविधि मध्य प्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत की जाएगी।)	50,000
2	ग्राम जमुनिया की आंगनबाडी को एक वर्ष के लिये गोद लिया जावेगा और उसका खर्च वहन किया जावेगा।	1,00,000
3	जमुनिया गांव में पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	50,000
4	जमुनिया ग्रामीणों हेतु गर्मी के मौसम में वाटर टैंकर द्वारा पेयजल की सुविधा	1,00,000
	योग	3,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, खमार, शीशम, बरगद, आम, महुआ,	6000

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

	एवं गैर खनन क्षेत्र	इमली, चिरोल, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, आम, शीशम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, गुआवा, पपीता, नींबू, हर्षा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
योग			7200

**5. Case No 9084/2022 M/s Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited, Shri Vijay Singh Verma, Director (Technical), Bhadbhada Road, Dist. Bhopal, MP - 462003 Prior Environment Clearance for Proposed Developemnt for Site A-1 Statue & Museum and Site A-2 Parking "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa, MP.Env. Consultant: In-Situ Enviro Care, Bhopal.**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Developemnt for Site A-1 Statue & Museum and Site A-2 Parking "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa, MP.

The case was presented by Env. Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In-situ Enviro Care , Bhopal on behalf of PP, wherein during presentation PP submitted that the project involves the construction/development of Statue of Oneness, Museum and Parking Facility. The maximum heights for the statue will be 60 M and for Building 12 M. The Total Land Area– 1,86,600.00 Sq. Mt. [18.66 Hect. (11.56 Hect. For Site A1 + 7.1 Hect. For Site A2)] Net Planning Area – 1,15,600.00 Sq.mt. Total Proposed Built up area - 55100.62 (A1 = 52346.5 Sq. Mt. + A2 = 2754.12 Sq.mt.).

PP further submitted that –

- The proposed project is planned in a plot measuring 18.66 Ha. (11.56 Hect. Site A1 +7.10 Ha. Site A2) on Khasra No. – 2/1 Part and 7/1 Part at Village – Mandhata, Teshil - Punasa, District - Khandwa (MP) .

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- The proposed land use for the project is open duly approved under the provisions as sanctioned by the T&CP authority. The site is located over Mandhata Revenue island on down stream of dam Narmada bank at Omkareshwar. Currently, the land is lying vacant & the aforesaid project shall permanently change the existing land use to spiritual. There would be an increase in spiritual /religious/tourism activities in the locality. The topography of the site area is flat top hilly terrain with slope trending.
- There will be scrapping off land to the tune of 85350 cum. during excavation activities, which will be used within the site for filling purposes & the additional mixed soil will be dumped on Municipal Site on payment basis. Buildings:- There are some existing structures on site which will be demolished as per C&D waste management rule 2016. Vegetation: Construction of Statue of Oneness, Museum and Parking Facility has been proposed. There is some existing structure on site, so demolition work is required. Approx. 85000 Cum. Debris waste will be generated during clearance of site, which will reused within project site as per C&D waste management rule 2016.
- No underground works is involved as no or tunneling activities is proposed except basement, foundation construction activity etc.
- Water requirement will be met from the Narmada water supply. There will be no impact on ground water regime by the project; however 2 no. of rainwater storage tank has been proposed of 672 Cum (Site A1) and 599 cum (Site A2).
- Power Requirement: Construction Phase: 1804.06 KVA. Occupancy phase: Connected Load: 9020 KVA. Maximum Demand: 5777 KVA. Transformer: 6400 KVA (1600 KVA X 4 No.) Backup Supply. UPS: 1500 KVA (3 X 500 KVA ) DG Set: 7000 KVA. (4 X 1250 KVA, 2 X 1000 KVA) will be used for back-up. Fuel Used: HSD Fuel.
- No storage of hazardous chemicals (as per MSIHC rules) will be done, apart from spent oil. Suitable management practice will be adopted for the same. It will be stored in HDPE drums and kept in covered rooms, under lock and key and will be sold to authorize vendors only. Specialized care shall be taken to prevent leaks and/or spills. HSD (Low Sulphure Variety) will be used for DG set. However, the quantity stored will be below the threshold limit specified by the MSIHC rules.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

### Salient Features of the Project

<b>Name of the Project</b>	<b>: "Statue of Oneness" Proposed Development for Site A-1 Statue &amp; Museum and Site A-2 Parking"</b>
<b>Coordinates of Site</b>	<b>: 22°14'58.11"N, 76° 9'0.72"E</b>
<b>Total Plot Area</b>	<b>: 1,86,600.00 Sq.Mt. (18.66 Ha.)</b>
<b>Proposed Built-Up Area</b>	<b>: 55100.62 Sq.mt. (A1 = 52346.5 Sq. Mt. + A2 = 2754.12 Sq.mt.)</b>
<b>Expected Population</b>	<b>: 50000 Nos.</b>
<b>Water requirement</b>	<b>: 1200 KLD (Permission from WRD is enclosed)</b>
<b>Source of Water</b>	<b>: Narmada Water Supply</b>
<b>Power requirement</b>	<b>: 5828.93 KVA</b>
<b>Source of Power</b>	<b>: MPSEB</b>
<b>DG Set</b>	<b>: 7000 KVA. (4 X 1250 KVA, 2 X 1000 KVA)</b>
<b>UPS</b>	<b>: 2000 KVA (4 X 500 KVA (1 Stand by Extra)</b>
<b>Project Cost</b>	<b>: 826.98 Cr.</b>

<b>Solar Panel</b>	<b>: 711 KW</b>
<b>Solid Waste Generation</b>	<b>: 13.5 TPD</b>
<b>Waste Water Generation</b>	<b>: 660 KLD ( 650 KLD WATER AND 10 KLD SLUDE)</b>
<b>Treated Waste Water Generation</b>	<b>: 650 KLD (480 KLD + 170 KLD)</b>
<b>Capacity of STP</b>	<b>: 800 KLD (600 KLD + 200 KLD)</b>
<b>Parking</b>	<b>: 1024 ECS</b>
<b>Height of the Statue</b>	<b>: 60 M (from ground)</b>
<b>Height of Building</b>	<b>: 12 M (Building)</b>
<b>Railway Station</b>	<b>: Omkareshwar Railway Station 11 Km (SW)</b>
<b>Air Port</b>	<b>: Indore Airport- 62.63 Km (NW)</b>
<b>Topography</b>	<b>: Hilly terrain</b>
<b>Annual Average Rainfall</b>	<b>: 777.60 mm</b>

### STATUTORY APPROVALS OBTAINED

<b>1</b>	<b>T &amp; CP APPROVAL- KHANDWA</b>	<b>163/JAN-434/NAGRANI/2022 Khandwa DATED 13/02/2022</b>
<b>2</b>	<b>COPY OF WATER SUPPLY NOC FROM WRD</b>	<b>122 dated 11/03/2022</b>

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

3	COPY OF MSW DISPOSAL NOC FROM OMKARESHWAR NAGAR PARISHAD	343/LO.NI./N.PARI./2022 OMKARESHWAR DATED 25/02/2022
4	COPY OF DISPOSAL OF EXTRA TREATED WATER NOC FROM OMKARESHWAR NAGAR PARISHAD	344/LO.NI./N.PARI./2022 OMKARESHWAR DATED 25/02/2022
5	FIRE NOC	440/LO.NI./N.PARI./2022 OMKARESHWAR DATED 10/03/2022

**AREA STATEMENT**

Statement of area				
A	Total Land (Site A1+A2)			
S. No.	Description	Area	Unit	%
1	Total Land Area	18.66	Hect.	
		46.11	Acre	
		186600.00	Sq.mt.	
2	Area under Govt. Road	8528.00	Sq.mt.	
3	Net Planning Area	178072.00	Sq.mt.	100
4	Open & Services	20526.00	Sq.mt.	11.53
5	Maximum Ground Coverage	71228.80	Sq.mt.	40.00
6	FAR	1:1.25	Ratio	
7	Maximum permissible Height	60	Meter	
8	Parking Area	47110.00	Sq.mt.	
9	Care Parking Space	1884	ECS	
Statement of area				
Total Land (Site A1) Land Sub Use: Statue & Museum				
	Description	Area	Unit	
	Total Land Area	11.56	Hect.	
		28.57	Acre	
		115600.00	Sq.mt.	
	Net Planning Area	115600.00	Sq.mt.	
	Open & Services	12716.00	Sq.mt.	

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

	Maximum Ground Coverage	42240.00	Sq.mt.	
	FAR	1:1.25	Ratio	
	Maximum permissible Height for Statue	60	Meter	
	Maximum permissible Height for Building	18	Meter	
	Car Parking Space	1884	ECS	
<b>Statement of Area</b>				
<b>Total Land (Site A2), Land Sub Use: Parking</b>				
	<b>Description</b>	<b>Area</b>	<b>Unit</b>	<b>%</b>
	Total Land Area	7.1	Hect.	
		17.54	Acre	
		71000.00	Sq.mt.	
	Area under Govt. Road	8528.00	Sq.mt.	
	Net Planning Area	62472.00	Sq.mt.	100
	Open & Services	7810.00	Sq.mt.	12.50
	Maximum Ground Coverage	24988.80	Sq.mt.	40.00
	FAR	1:1.25	Ratio	
	Maximum permissible Height for Building	12	Meter	
	Parking Area	47110.00	Sq.mt.	
	Car Parking Space	1884	ECS	

PP further submitted that there are 1048 trees present on site out of these 418 trees will be uprooted. PP further submitted that they have obtained FC clearance issued by MoEF&CC vide letter dated 07/01/22. In the proposed project 72464.5 Sq.mt. (56,622 Sq.mt. Site A1 + 15842.5 Sq.mt. Site A2) areas is allocated for greenbelt/landscape development in which 1845 trees have been proposed in plantation scheme. As submitted by PP out of 1398 trees in existence on site 418 trees are proposed to be uprooted. Considering 10 times plantation/tree uprooting, additionally 4180 plants shall have to be planted. Committee after deliberations recommends insitu plantation of 6025 (4180+1845) species shall be carried out for this project. During discussion, PP also informed that additional land of 36.00 ha is allocated on the northern side of the project site A-1 where they are planning thick green belt development through root zone technology and plantation of bamboo. Thus, insitu

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

plantation of 6025 trees shall be carried out in the proposed project area at site A1 & A2 and additional plantation of bamboo in 4316 numbers in adjacent 36.00 ha land. Hence 10,341 species as mentioned in the plantation scheme shall be planted. Project site has a flat top hilly terrain with slope tending towards North to South and West to East. The area under study falls in Seismic Zone – III, Which is a moderate damage risk zone. PP submitted that earthquakes resistance building meeting criteria of ZONE IV are designed for proposed areas in block A-1 area and for remaining area earthquakes resistance building designs is proposed which is compatible to Zone III. PP also stated that no R&R is proposed A-1 & A-2 area and till date no construction activities have been initiated in this project. Being located on the close proximity of Narmada River Catchment Area, committee recommended that project shall be Zero Liquid Discharge and also no Municipal Solid Waste or other wastes (such as E-waste, Battery Waste, Waste polythene etc) shall find its way to the Narmada River. PP shall also install Two Online Continuous Water Quality Monitoring Stations (one on the upstream of the project site and other on the downstream of the project site and locations of these monitoring stations shall be decided in consultation of MP Pollution Control Board) and their results shall be displayed on the banks of Narmada River for awareness of local residents & devotees. Committee further suggested that the runoff of the proposed project area shall be collected and discharged in the municipal sewer line and be treated in proposed common STP and to avoid vehicular emissions on the hill top and rush of vehicles PP shall explore the possibility of providing e-vehicles/CNG based vehicles from base parking area/station to the proposed museum parking area at A-2. During discussion committee also suggested that PP shall also explore the possibility of displaying fossils in proposed museum found in the Narmada River Basin Area to enrich the knowledge of the devotees/visitors and Plantation of native species found on the banks of Narmada River from Amarkantak, MP to Alirajpur, MP shall be preferred through competent agency having knowledge regarding flora & fauna of MP to address the issue of biodiversity, ground water recharge, climate change and minor forest produce. The Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project.

- Is any R& R plan proposed from the project area?
- Revised details of C& D waste generation & their handling and disposal plan.
- What is the carrying capacity of museum and maximum people it can hold in a day?
- Will it be ZLD project how treated effluent of 700 KLD will be utilized, so no effluent shall be discharged in the Narmada River?
- Additional measures proposed for approaching site such as rope way, cable bridge, cable car etc.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- Regulatory mechanism proposed for preventing rush of vehicles on hill top during peak days. If any related study is conducted shall be submitted.
- Surface run-off management plan and how storm water will be managed.
- Proposal for 4180 additional plantation w.r.t. 418 trees are proposed for felling.
- Revised EMP with appropriate budget as suggested by committee.
- Traffic management plan and retention wall as discussed during presentation.
- Commitment that no construction is initiated on project site till date.
- Clarification regarding the allotted land, is it forest or revenue land.
- If it is revenue land, why forest clearance documents are uploaded with case file.
- In Ec application form, total tree cutting proposed is 607 whereas in presentation it is 418, justification?
- Copy of tree cutting permission obtained from competent authority.

PP vide letter dated 29.03.2022 has submitted the query reply on above issues which was placed before the committee wherein committee observed that as per the reply and commitment of PP, the allotted land is revenue land and as a proof copy of Khasra Panchshala is attached. PP informed that by mistake they have uploaded the FC of other project (Gurukul, Institutional Project). PP Further submitted that total tree to be uprooted are 418 and have obtained approval of competent authority for tree uprooting issued vide letter dated 24/03/22. However, due to typographical error figure of 607 was mentioned in the EC application and they are appending revised Form-1 with this reply. The identified agency for tree uprooting is PWD and work will be envisaged to them after EC. The reply submitted by PP on other issues was discussed and found satisfactory and acceptable. The presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Development for Site A-1 Statue & Museum and Site A-2 Parking "Statue of Oneness" at Village - Mandhata, Tehsil - Punasa, Dist. Khandwa MP for the maximum heights for the statue will be 60 M and for Building 12 M. The Total Land Area– 1,86,600.00 Sq. Mt. [18.66 Hect. (11.56 Hect. For Site A1 + 7.1 Hect. For Site A2)] Net Planning Area – 1,15,600.00 Sq.mt. Total Proposed Built up area - 55100.62 (A1 = 52346.5 Sq. Mt. + A2 = 2754.12 Sq.mt.). Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

**Statutory Compliance**

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Archiological Survey of India & State Archiological
- vii. The conditions stipulated in T&CP approval dated 13/02/22 shall be complied by PP.
- viii. Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- ix. If any central or state recognized monuments falling in the project area the PP should take permission / NOC from the concerned competent authority.
- x. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- xi. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- xii. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

## **II. Air Quality Monitoring and preservation**

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets as 7000 KVA (4 X 1250 KVA, 2 X 1000 KVA & UPS 2500 KVA (5 X 500 KVA) are proposed as source of backup power should be of

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from Diesel power generating sets as 7000 KVA. (4 X 1250 KVA, 2 X 1000 KVA shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

### **III. Water quality monitoring and preservation**

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 1638 KLD. Whereas fresh water is 851 KLD (634 KLD for A-1 & 217 KLD for A-2). Waste Water Generation- 800 KLD (600KLD from A-1 site & 200 KLD from A-2 site ) out of which Treated water shall be 650 KLD (480KLD from A-1 site STP & 170 KLD from A-2 site STP ) water and 10 KLD sludge. Treated water shall be used for horticulture and flushing purposes.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 11% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016.
- xii. 02 nos. of Rain Water storage tanks will be constructed for storage of rain water. The storage capacity of each tanks about 672 m<sup>3</sup> & 599 m<sup>3</sup> respectively. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- xiii. The Rain Water storage tanks will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xv. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xvii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.
- xviii. Sewage shall be treated in the SBR based 02 nos. of STP Capacity - 800 KLD (600 KLD (A-1 site ) + 200 KLD (A-2 site). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xix. The waste water generated from the project shall be treated in 02 STP of 800 KLD (600 KLD (A-1 site) + 200 KLD (A-2 site). Capacity (based on SBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xx. Being located on the close proximity of Narmada River Catchment Area, project shall be Zero Liquid Discharge and also no Municipal Solid Waste or other wastes (such as E-waste, Battery Waste etc) shall find its way to the Narmada River.
- xxi. PP shall also install Two Online Continuous Water Quality Monitoring Stations (one on the upstream of the project site and other on the downstream of the project site) and their results shall be displayed on the banks of Narmada River for awareness.
- xxii. The runoff of the proposed project area shall be collected and discharged in the municipal sewer line and be treated in proposed common STP.
- xxiii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxiv. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxv. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

**IV. Noise monitoring and prevention**

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

**V. Energy Conservation measures.**

- i. The Power would be fulfilled from MPEB. The total maximum demand would be 5828.93 KVA while connected load would be 9260.5 KVA.
- ii. The 711 KW Renewal Energy shall be generated through Solar Panel on Parking Area i.e. form A2 Site shall be used in-house.
- iii. Energy consumption reduced by use following points.
  - Level controller for pumps.
  - Timer for street & common lighting.
  - Designing of peak & non peak circuits for common area.
  - Reduced in load due to using the LED Lights.
  - Distribution Transformer are 3 star Rated as per BEE norms.
  - Solar powered street lights shall be used to conserve energy.
- iv. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- v. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- vi. PP shall explore the possibility of providing e-vehicles/CNG based vehicles from base parking area/station to the proposed museum parking area to avoid vehicular emissions on the hill top and rush of vehicles.
- vii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

- viii. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- ix. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- x. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

#### **VI. Waste Management**

- i. Total solid waste generated will be around 13.5 TPD (13 TPD Biodegradable and 0.5 TPD Non-Biodegradable Waste) Biodegradable & Non-Biodegradable waste will be segregated at source in accordance with MSW (M&H) Rules, 2016.
- ii. 7771.0 Cu.m. C&D waste would be generated and reused within site for filling and leveling of site as per Norms.
- iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

**VII. Green Cover**

- i. In the proposed project 72464.5 Sq.mt. (56,622 Sq.mt. Site A1 + 15842.5 Sq.mt. Site A2) areas is allocated for greenbelt/landscape development in which 1845 trees have been proposed in plantation scheme. As submitted by PP out of 1398 trees in existence on site 418 trees are proposed to be uprooted. Considering 10 times plantation/tree uprooting, additionally 4180 plants shall have to be planted. Committee after deliberations recommends insitu plantation of 6025 (4180+1845) species shall be carried out for this project. During discussion, PP also informed that additional land of 36.00 ha is allocated on the northern side of the project site A-1 where they are planning thick green belt development through root zone technology and plantation of bamboo. Thus, insitu plantation of 6025 trees shall be carried out in the proposed project area at site A1 & A2 and additional plantation of bamboo in 4316 numbers in adjacent 36.00 ha land. Hence 10,341 species as mentioned in the plantation scheme shall be planted. Broad leaves plantation shall be preferred on the parking side.
- ii. Plantation of native species found on the banks of Narmada River from Amarkantak, MP to Alirajpur, MP shall be preferred through competent agency having knowledge regarding flora & fauna of MP to address the issue of biodiversity, ground water recharge, climate change and minor forest produce.
- iii. Also explore possibility to developing a medicinal garden & displaying fossils in proposed museum found in the Narmada River Basin Area to enrich the knowledge of the devotees/visitors.
- iv. Since the proposed site is table top of the island and extreme slope is towards the main stream of Narmada River thus highly precisely soil conservation work and vegetation cover shall be carried out along the River.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- v. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- vi. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- vii. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

### **VIII Transport**

- i. PP will explore the possibility of providing green vehicles for base parking area to the museum parking area to avoid station vehicular emission at top of the hill.
- ii. PP shall explore additional measures proposed for approaching site such as rope way, cable bridge, cable car etc.
- iii. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
  - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
  - b. Traffic calming measures.
  - c. Proper design of entry and exit points
  - d. Parking norms as per local regulation
- iv. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- v. Parking's arrangement for A-1 & A-2 site is 1884 ECS each.
- vi. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

**IX. Human health issues**

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

**X. EMP & Corporation Environment Responsibility**

- i. For Environment Management Plan PP has proposed during construction phase Rs. 742.62 Lakhs as capital and Rs. 53.50 Lakhs as recurring cost for this project. And during operation phase Rs. 1357.83 Lakhs as capital and Rs. 124.00 Lakhs as recurring cost for this project out of which PP has also proposed following activities under Corporate Environment Responsibility (CER) with budget.

Component	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
Providing Water Coolers	3,00,000.00	1,00,000.00
Provide Solar Street lights in the nearby area	20,00,000.00	3,00,000.00
Support	4,00,000.00	2,00,000.00
Plantation along approach roads in a scientific manner	30,00,000.00	8,00,000.00

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

**XI. Miscellaneous**

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the project shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 etc along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

**6. Case No 9082/2022 Shri Jagdish S/o Shri Ramchandra, Village - Jabardi, Tehsil - Pachore, Dist. Rajgarh, MP Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 284 दिनांक 08/03/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 11.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 155 एवं पूर्व दिशा में 412 मीटर पर पक्का रोड़ है, पश्चिम दिशा में 435 मीटर पर कुछ मकान है। खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 850 मीटर पर तालाब है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरुम खनिज होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जनवरी, 2022 से बेसलाईन डाटा मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर दिया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 155 एवं पूर्व दिशा में 412 मीटर पर पक्का रोड़ है, पश्चिम दिशा में 435 मीटर पर कुछ मकान है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 850 मीटर पर तालाब है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

**7. Case No 9085/2022 M/s Adavita Developers and Promoters Pvt. Ltd, K-6, First Floor, Khandelwal Complex, Opp. UBI Near Guljar Hotel, Madan Mahal, Dist. Jabalpur, MP . Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" (Total Plot Area = 22271 sqm, Total Built-up Area = 66058.54) at Village - Zone-I Garha, Colony Sagda Tripuri, Tehsil & Dist. Jabalpur, MP. Env. Consult.:- M/s. Ambiantal Global Private limited. (Violation TOR).**

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" (Total Plot Area = 22271 sqm, Total Built-up Area = 66058.54) at Village - Zone-I Garha, Colony Sagda Tripuri, Tehsil & Dist. Jabalpur, MP.

The case was presented by the PP and their Env. Consultant Env. Consult. Shri Sandhu M/s. Ambiantal Global Private limited in the, wherein it was observed that this is a violation project and construction of few blocks have been completed. PP submitted following details of the project:

- M/s Adavita Developers and promoters Pvt. Ltd. has proposed the Group Housing Project “ Shree Ram Heights” Khasra No. 150/2,150/1, 151,152/1,154/2, 153,152/2 Zone-1(Garha), Colony :- Sagda Tripuri, Jabalpur, Madhya Pradesh.
- The Proposed estimated built-up area of 22271.00 m<sup>2</sup> . Total built up Area is 66,058.54m<sup>2</sup> As per the EIA Notification and its amendment, the project is falling in the category 8 (b).
- Group housing project will provide good infrastructure facilities and state of the art technology and will be developed taking into account eco friendly features in order to provide a healthier environment
- The proposed site has been earmarked for residential purpose as per master plan of Jabalpur -2021. Therefore no permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan) will occur.

During presentation it was observed by committee through Google image as per the co-ordinates provided by that prior to the construction of project as per previous Google image of 03/2013 some trees (approx. 15) were in existance on the project site and all have been uprooted in the previous image of 12/2013 and area has been cleared. Committee during presentation asked PP whether for trees uprooting approval of competent authrotiy was obtained or not and what was the land use at that time for which PP & consultant were unaware and seeked time to answer the reply and requested

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

that they may be given some time to address this query. Committee after deliberation decided that PP shall collect all the relevant information within a week time and this case shall be listed in the next SEAC meeting scheduled in the first week of Arril, 2022.

**8. Case No 9074/2022 RAGHURAJ SINGH village Sarsaini Tehsil Joura District Morena,,Morena,Madhya Pradesh-476001 Prior Environment Clearance for Stone (Gitty) Quarry in an area of 1.61 ha. (25000 Tonne per annum) (Khasra No. 34), village Bidhniya Tehsil Datia District Datia,,Datia, Madhya Pradesh-475661**

This is case of Stone (Gitty) Quarry . The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 34), village Bidhniya Tehsil Datia District Datia (M.P.) 1.61 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 561वीं बैठक दिनांक 21/03/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 79 दिनांक 31/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत खदानों का एवं प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 3.61 हेक्टेयर है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 70 मीटर पर रोड हैं तथा पूर्व दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड़ है । इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर नहर है एवं लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ भी लगे हुए है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 08 पेड़ काटे जावेंगे तथा उनके एवज में 80 पेड़ अतिरिक्त लगायेंगे । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ लीज क्षेत्र के उत्तर पश्चिम 75 मीटर नहर है, अतः 25 मीटर का सेट-बैक (नॉन माइनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेंप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 घनमीटर प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.36
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.05 लाख :-

सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम बिड़निया में पीनापानी के लिए बोरवैल खुदवाकर लिफ्टिंग पम्प लगाया जायगा और उसओवरहड टैंक में पाइपलाइन सजोड़ा जायगा।	1,05,000
योग	1,05,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित स्थान	लगाए जाने वाले पौधों के प्रकार	मात्रा
बैरियर जोन	नीम, सीताफल, खमार, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलझी, सिस्सो आदि।	530
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, अशोक आदि	220
ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1250
<b>कुल योग</b>		<b>2,000</b>

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

**9. Case No 9077/2022 M/s Shiv Minerals, Director, Shri Ajay Pal Singh Parmer, 6th KM Sagar Road, Dhadari, PO & Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Red Ochre Quarry in an area of 1.489 ha. (62,359 TPA) (Khasra No 51/1), Village - Kota, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Red Ochre Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 51/1), Village - Kota, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.489 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2352 दिनांक 27/7/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र से 120 मीटर की दूरी वन है, अतः संबंधित संभागायुक्त समिति की बैठक दिनांक 01/10/21 में अनुशंसा प्राप्त की गई है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ दिख रहे। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्खनन में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में वर्ष 2014-15 तक उत्खनन हुआ है और उसके बाद से पर्यावरणीय स्वीकृति न होने के कारण बंद है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ संभागायुक्त समिति की बैठक दिनांक 01/10/21 के कार्यवाही विवरण की प्रति ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र कि संभागायुक्त समिति की बैठक दिनांक 01/10/21 में की गई अनुशंसाओं का पालन किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेड ओकर -62,359 टन प्रति वर्ष ।

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.52 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख :-

Sr. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/year)
1	Contribution in Aanganwadi Centre Patra under "Poshan Aahar Yojna"	1,50,000.00
<b>Total</b>		1,50,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, सीताफल, करंज, शीशम, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	700
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	अचार, बेल, अमलतास, नीम, खमेर, कचनार, खेर, करंज, पीपल, शीशम, आम, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
योग			2200

**10. Case No 9080/2022 Shri Sumit Kanoongo Lease Owner, R/o- Prayag Park, Sanawad, District - Khargone (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.990 ha. (19,000 cum per annum) (Khasra No 463/1), Village -Gandhawad, Tehsil - Segaon, Dist. Khargone (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 463/1), Village - Gandhawad, Tehsil - Segaon, Dist. Khargone (MP) 1.990 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6054 दिनांक 03/2/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 3.990 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 107 मीटर पर और उत्तर दिशा में 110 मीटर पर नहर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा तथा ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा तथा ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 19,000 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 12.74 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 06.88 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख :-

क्रं.	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	ग्राम गंधावाडा के ऑगनवाड़ी केन्द्र में 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	50,000
2	ग्राम मुल्तान पी.एच.सी. में 200 औषधीय पौधों का रोपण एवं सिंचाई व्यवस्था।	30,000
योग		80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	गंधावाडा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	980
4	शासकीय विद्यालय गंधावाडा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
योग			2300

**11. Case No 9079/2022 Shri Prakash Gurbele, Owner, Ward No. 11, Bhatera Road, Dist. Balaghat, MP - 481001 Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 4.576 ha. (Blockable Granite - 2919 cum per annum, Unblockable Granite - 26271 cum per annum) (Khasra No 139), Village - Kulpa, Tehsil - Lanji, Dist. Balaghat (MP)**

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 139), Village - Kulpa, Tehsil - Lanji, Dist. Balaghat (MP) 4.576 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 775 दिनांक 10/2/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य 04 (लीज स्वीकृति आवेदित है) खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 21.096 हे. होता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण एसईआईए से बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी द्वारा 500 मीटर में दी गई जानकारी अनुसार लीज स्वीकृति हेतु अन्य 04 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया है, जो प्रचलन में है तथा यह सभी प्रॉस्पेक्टिंग लीज है जो पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में नहीं आयेगी। अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है तथा इसी आधार पर एसईआईए ने बी-2 का माना है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि खनन क्षेत्र से 100 मीटर दूरी पर मरघट है अतः समिति ने सुझाया कि 05 पौधे (बरगद, पीपल, पाकड़, नीम एवं गूलर के) मरघट के चारों ओर लगा दिये जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः 40 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) छोड़े जाने के निर्देश समिति द्वारा दिए गए तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन ग्रेनाइट-2919 घनमीटर/वर्ष एवं

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

एम-सेड-26,271 घनमीटर/वर्ष (Unblockable Granite) हेतु किया है किंतु लीज स्वीकृति आदेश क्रमांक 15725 दिनांक 16/12/20 में अनब्लॉकेबल ग्रेनाइट से एम-सेड बनाने का उल्लेख नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक बताया कि उन्हें सिर्फ ग्रेनाइट माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए। प्रस्तुतीकरण पश्चात् निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र कि उन्हें सिर्फ ग्रेनाइट माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए।
- ✓ पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड़ है अतः 40 मीटर का सेट-बैक (नॉन माइनिंग जोन) छोड़े जाने के निर्देश समिति द्वारा दिए गए तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट – 2919 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.52 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख :-

क्र.	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	शासकीय हाई स्कूल कुल्पा में 30बेंच व 10कुर्सियों की व्यवस्था	35,000
2	कुल्पा आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार का वितरण	1,15,000
4.	योग	1,50,000 / -

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5493 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमण्ड, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमण, चिरोल, पुत्रंजीवा, करंज, जंगल जलझी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
3	गैर खनन क्षेत्र	खमण, बीजा, करंज, कुसुम, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (बीज बुवाई—नीम, करंज, प्रोसोपिस)	700
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बख, आँवला, हरी, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार, बहणा, बख एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
5	ग्राम पंचायत का सहयोग से ग्राम पंचायत कुल्पा जिला बालाघाट का चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बख, आँवला, हरी, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1493
6	ग्राम पंचायत कुल्पा का प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	पुत्रंजीवा, करंज, कचनार, आँवला, सीताफल, कबीट एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
योग			5493

**12. Case No 9081/2022 Shri Abdul Sadik Qureshi, Owner, Ward No. 14, Warseoni, Dist. Balaghat, MP - 481331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5,613 cum per annum) (Khasra No 01, 411, 514, 508/2), Village - Dongariya, Rengakhirl, Jabartola, Tehsil - Waraseoni, Dist. Balaghat (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 01, 411, 514, 508/2), Village - Dongariya, Rengakhirl, Jabartola, Tehsil - Waraseoni, Dist. Balaghat (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर,

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

(खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1405 दिनांक 23/11/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 314 मीटर पर पक्का रोड़ एवं 431 मीटर पर नहर है, उत्तर-पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर आबादी एवं दक्षिण-पूर्वी दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र 1.00 हेक्टेयर करने के लिए लीज 02 भागों में स्वीकृत की गई है। खदान के चारों ओर 02-03 अन्य खदान खुदी हुई दिख रही है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से कोई भी संचालित नहीं है और काफी पुरानी खदानें हैं। समिति द्वारा गूगल की बैक इमेज हिस्ट्री से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि खदान के आसपास जो खुदा क्षेत्र दिख रहा है वह काफी पुराना है तथा लगभग वर्ष 2010 के पूर्व से खुदा हुआ दिख रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 100 मीटर दूरी पर तालाब है, जिसके प्रोडक्टेक्शन हेतु गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का प्रावधान किया गया है। लीज क्षेत्र के एक भाग में 04-05 पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र में खनन प्रस्तावित नहीं है तथा इस क्षेत्र में साइट आफिस व अन्य सुविधाये विकसित की जावेगी। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ लीज क्षेत्र के एक भाग में 04-05 पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र में खनन प्रस्तावित नहीं है तथा इस क्षेत्र में साइट आफिस व अन्य सुविधाये विकसित की जावेगी, अतः नॉन माईनिंग एरिया दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस में।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,613 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कंपीटल राशि रु. 07.57 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.55 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.75 लाख :-

क्रं	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	स्कूल एवं आंगनवाड़ी कैंपस में 50 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति – नीम,मौलश्री,कचनार,कदम आदि।	25,000

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

3	रैगाझिरी गाँव क आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष तक पोषण आहार	50,000
योग		75,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, खमेर, बीजा, कुसुम, सीताफल एवं एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	950
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, जगलजलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
3	विद्यालय में वितरण हेतु	मौलश्री, कचनार, कदम, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
योग			1200

**13. Case No 9083/2022 Shri Ranjeet Soni, Devra, Tehsil & Dist. Dindori, MP - 481880**  
**Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5000 cum per annum) (Khasra No 203, 204), Village - Hinota Mal, Tehsil - Dindori, Dist. Dindori (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 203, 204), Village - Hinota Mal, Tehsil - Dindori, Dist. Dindori (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 700 दिनांक 23/2/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 240 मीटर पर नाला है, पूर्व दिशा में 160 मीटर पर नाला है, पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रोड़ है, पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर एच.टी. लाईन एवं पश्चिम दिशा में 120 मीटर पर टावर स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज खनिज क्षेत्र में 02 पेड़ हैं जिन्हें काटे जाने का

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

प्रस्ताव नहीं है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 5000 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.70 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.45 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख :-

क्र.	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
4. 1	स्कूल कंपस में 100 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति – नीम,मौलश्री,कचनार,कदम, पुत्रन्जीवा।	50,000
3	हिनोता माल गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष तक पोषण आहार	50,000
	योग	1,00,000

नुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, बरगद, करंज, महुआ, चिरोल, सीताफल एवं एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, चिरोल, करंज, महुआ, जगलजलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	विद्यालय में वितरण हेतु	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
		योग	1200

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

**14.प्रकरण क्रमांक 8999/2022 - श्रीमती मनुप्रिया यादव, भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन क्वेरी-8,512 एवं सिलेबिल ओवरवर्डन 5,488 मी.<sup>3</sup> ग्राम बबुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, ग्राम बबुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 17/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर दिशा में 280 मीटर पर तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 480 मीटर पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान या पाया गया कि उत्तर-पश्चिम दिशा में एक शवदाह का शेड स्थित है, अतः उसे 60 मीटर का सेड-बैक छोड़ दिया जाये तथा सेट-बैक क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाये। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपणयोजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 8512 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष तथा ओवर वर्डन -5488 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 05.55 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 00.60 लाख :-

आगमी 05	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
---------	------------------------------------	--------------

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

वर्ष तक		
खदान क्षत्र का पास स्थित मुक्ति धाम परिसर में हैंडपंप लगवाया जायगा		60,000/-
योग		60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलझी, सिस्सू, सफ़ाई कैस्टर, करंज, आवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1350
2	परिवहन मार्ग में (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	करंज, महुआ, चिरोल, पुत्रजीवा जंगल जलझी, नीम, मोलश्री सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	500
3	खदान क्षत्र में प्रस्तावित गैर खनन क्षत्र में	आवला, करंज, महुआ, चिरोल, जंगल जलझी, नीम, सबूल सिस्सू पुत्रजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	850
4	खदान क्षत्र का पास स्थित मुक्तिधाम में	पाकड़ मोलश्री कदम बरगद सफ़ाई कनक पीपल करंज, आवला, चिरोल, नीम, मोलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
		कुल वृक्षारोपण	3200

उपरोक्त प्रकरण 555वीं सेक की बैठक दिनांक 24/2/22 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण को परिवेश पोर्टल पर सेक को परीक्षण कर पुनः अनुशंसा करने हेतु ऑनलाईन वापिस भेजा गया है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं एसईएसी की 555वीं बैठक दिनांक 24/2/22 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा अंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 17/11/2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होना दर्शित है। यद्यपि अनुमोदन खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार कई

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

अन्य खदान का होना परिलक्षित है जिसमें पूर्व से ही उत्खनन का कार्य किया गया है जिसके कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है ।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एसईएसी द्वारा 07 दिवस में प्रकरण का परीक्षण कर पुनः अनुशंसित किया जाये । तदनुसार प्रकरण आज दिनांक 29/3/22 को एसईएसी के समक्ष पुनः परीक्षण हेतु प्रस्तुत है ।

समिति द्वारा पुनः प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा पाया कि समिति ने प्रकरण के साथ प्रस्तुत सभी सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर इस प्रकरण में अपनी अनुशंसा सिया को प्रेषित की थी । समिति ने पाया कि इस प्रकरण के 555वीं सेक बैठक दिनांक 24/2/22 में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के चारों ओर के संवदेनशील लक्षणों का अवलोकन कर, प्रकरण में अपनी अनुशंसा की गई थी ।

यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के चारों ओर की स्थिति का पुनरावलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट होगा कि खदान क्षेत्र के उत्तर व उत्तर-दक्षिण क्षेत्र में जो खुदा हुआ दिख रहा है, वह पुरानी गूगल इमेज के अनुसार नवम्बर, 2010 से वहाँ पर स्थित है तथा काफी पुराना है । संभवतः यह पुरानी खदानें होगी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी होगी इसलिए एकल प्रमाण पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा इनका उल्लेख नहीं किया है । समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान इन सभी कारकों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तथा यदि स्वीकृत खदान के आसपास कोई पूर्व की उत्खनन गतिविधियाँ ध्यान में आती है तो गूगल इमेज से उनकी पूर्व की अवधि का आंकलन कर निर्णय लिया जाता है । कृपया मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 108 दिनांक 31/1/22 की कण्डिका-6 का अवलोकन करें जिसमें यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि *“वन विभाग एवं अन्य विभागों से लिखित एन.ओ.सी. प्राप्त करने के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जहाँ तक संभव हो, तकनीकी/गूगल मेप का उपयोग कर निर्णय लिया जाये”*।

इस प्रकरण में समिति पुनः गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के चारों ओर की स्थिति का अवलोकन कर पूर्व में 555वीं सेक बैठक दिनांक 24/2/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है ।

**15. Case No. – 6311/2019 Shri Abhishekh Kumawat, M/s Sanwaliyarundi Stone Deposit, Dongre Nagar, Dist. Ratlam, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (14,938 cum per annum) (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sanwaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sanwaliyarundi, Tehsil -

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 376वीं दिनांक 01/07/2019 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के उत्तर दिशा में लीज बाउण्ड्री से लगी हुई एक कच्ची रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनकी खदान कार्यरत न होने के कारण अभी यह कच्चा रोड़ उनकी लीज के पास निकल रहा है तथा वास्तविक रूप से 10 मीटर दूरी पर है । समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि चूँकि वर्तमान परिस्थिति में कच्चा रोड़ विद्यमान है, अतः कच्चे रोड़ से के पास वाले 7.5 मीटर बैरियर जोन में सबसे पहले तीन कतारों में वृक्षारोपण किया जाये तथा उनके पास ही साइट आफिस व अन्य सुविधाओं का विकास किया जाये । इसी प्रकार खदान के पूर्वी दिशा 90 मीटर पर नदी तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे : सेप्टिक टैंक का निर्माण, पानी की व्यवस्था, गांव के मंदिर में विकास कार्य तथा वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित जल खतप योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 22/3/22 को परिवेश पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन — 14,938 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष तथा ओल्डर वर्डन —5488 मी.<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 06.76 लाख प्रति वर्ष ।

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.95 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम सांवलियारुण्डी में मंदिर एवं वृक्षारोपण का विकास किया जायेगा।</li> <li>ग्राम सांवलियारुण्डी में सबमर्सिबल पंप के साथ 2 हैंडपंप की स्थापना करवाया जायेगा।</li> <li>सांवलियारुण्डी गांव से शीतलामाता मंदिर और नाला तक सड़क निर्माण के लिए गिट्टी और मुरुम का योगदान किया जायेगा।</li> </ul>	30,000 65,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>सेप्टिक टैंक का निर्माण</li> <li>सड़क निर्माण</li> <li>जल छिड़काव प्रणाली की सुविधा की व्यवस्था</li> <li>पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी</li> <li>अधिक से अधिक वृक्षारोपण</li> <li>पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद ग्राम सांवलियारुण्डी के 22 लोगों को रोजगार दिया जायेगा।</li> </ul>	पहले से ही ईएमपी में शामिल है।
<b>योग</b>	<b>95,000</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कस्टार, जंगल जलेबी, चिरौल, आवंला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	परिवहन मार्ग में (पेडो की न्यूनतम ऊँचाई - 01 मीटर)	शीशम, अमलतास, जामुन, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
3	ग्रामपंचायत सांवलियारुण्डी के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	इमली, आवंला, आम, बेल, नींबू, महुआ, सिस्सू, जामुन, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	1800
कुल			4800

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

### 16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला शिवपुरी

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 3581 दिनांक 25/03/22 के माध्यम से शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को दिनांक 28/3/22 को प्राप्त हुई। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 28/03/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 में शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि :-

- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र. ने पत्र क्रमांक-3-6/खनि/615/2022, दिनांक 22/3/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का गठित समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।
- ✓ इसी प्रकार कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र. ने पत्र क्रमांक-3-6/खनि/653/2022, दिनांक 25/3/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर अपलोड किया गया है किंतु आज दिनांक 25/3/22 तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। यदि कोई सुझाव प्राप्त होते हैं तो उनको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।
- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 3581 दिनांक 25/03/22 के माध्यम से शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई हैं परंतु बिंदु क्रमांक-22 (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है, में शिवपुरी जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है। अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट किया जाये एवं बिंदु क्रमांक-22 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) उसमें समाहित की जाये।
- ✓ समिति का मत है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर अपलोड किया गया है किंतु कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र. ने पत्र क्रमांक-3-6/खनि/653/2022, दिनांक 25/3/22 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको दिनांक 25/3/22 तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं अतः यदि इस संदर्भ में कोई सुझाव प्राप्त होते हैं तो सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन, 2016, एनफोर्समेंट एण्ड

**562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 29 मार्च 2022**

मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेंड माईनिंग, 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप उनको भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूंकि शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा दिनांक 21/3/22 की बैठक में किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ शिवपुरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
  - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be  $1/4^{\text{th}}$  or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)  
c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
  - After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- ‘C’**

**Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
  - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 29 मार्च 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

## 562वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.  
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।  
**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।  
**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।  
**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –  
**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।  
**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.  
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.  
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.  
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.